परेशानी का सामना करना पड़ा था, तो दूसरी ओर झारखंड

और बिहार में बारिश कम हुई. इसके कारण झारखंड के बड़े

इलाके में धान के रोपा में समस्या आयी थी. समस्या केवल

कम या अधिक बारिश की नहीं है. बारिश होती भी है. तो

हम जल संरक्षण नहीं करते हैं. जो हमारे तालाब हैं, उनको

हमने पाट दिया है. शहरों में तो उनके स्थान पर बहुमंजले

अपार्टमेंट्स और मॉल खड़े हो गये हैं. झारखंड की ही

मिसाल लें. यहां साल में औसतन 1400 मिलीमीटर बारिश

होती है. यह किसी भी पैमाने पर अच्छी बारिश मानी जायेगी,

लेकिन बारिश का पानी बह कर निकल जाता है, उसके

संचयन का कोई उपाय नहीं है. इसे चेक डैम अथवा तालाबों

के जरिए रोक लिया जाए, तो सालभर खेती और पीने के पानी

# पाकिस्तान का उकसावा

मरान खान सरकार से यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन यह उम्मीद लगातार टूटती जा रही है. बीते हफ्ते लाहौर में आतंकी सरगना हाफिज सईद को खुलेआम कश्मीर के नाम पर भारत के खिलाफ जहर उगलने की मंज़्री देकर पाकिस्तान सरकार ने यही इंगित किया है कि उसकी नीतियां पिछली सरकारों से अलग नहीं हैं. सईद संयुक्त राष्ट्र द्वारा आतंकवादी करार दिया जा चुका है और उसी ने मुंबई हमले की साजिश रची थी. हालांकि भारत ने जोरदार विरोध जताते हुए पाकिस्तान से मांग की है कि वह अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ किसी गतिविधि की अनुमति न दे, पर इसका शायद ही कोई असर होगा. पिछले हफ्ते ही ब्रिटिश संसद के परिसर में आयोजित एक भारत-विरोधी आयोजन में पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हाफिज सईद की तरह ही बातें कीं. सितंबर में इमरान सरकार में मजहबी मामलों के मंत्री नूरूल हक कादरी ने हाफिज सईद के साथ एक ही मंच पर खड़े होकर भारत-विरोधी बयानबाजी की थी. दिसंबर में वहां के गृह राज्यमंत्री शहरयार खान अफरीदी ने हाफिज सईद और

2018 में नियंत्रण रेखा और सीमा पर पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम के उल्लंघन की २,९३६ घटनाएं हुई हैं. पंद्रह सालों में यह सबसे बड़ी संख्या है.

उसके गिरोहों के प्रति समर्थन की खुली घोषणा की थी. साल 2018 में दोनों देशों की सीमा और नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान द्वारा युद्धविराम के उल्लंघन की 2,936 घटनाएं हुई हैं. यह संख्या 2017 की 971 घटनाओं से तीन गुनी अधिक है. पंद्रह सालों में यह सबसे बड़ी संख्या है. इससे यही जाहिर होता है कि 2003 में एक-दुसरे पर गोलाबारी न करने का समझौता बेमानी हो चुका है. उल्लेखनीय है कि दोनों देशों के बीच 3,323 किलोमीटर लंबी सीमा है, जिसमें 221

किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा और 740 किलोमीटर नियंत्रण रेखा जम्मु-कश्मीर में है. कश्मीर में घुसपैठ के जरिये आतंकी भेजने और अलगाववादियों को शह देने की पाकिस्तानी नीति भी बदस्तूर जारी है. इसके अलावा नशीले पदार्थों की तस्करी तथा अपराधियों को शरण देने की उसकी परिपाटी भी नहीं बदली है. दशकों से भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तथा द्विपक्षीय संवादों में यह कहता रहा है कि आतंकवाद वास्तव में पाकिस्तान की विदेश, रक्षा और आंतरिक नीतियों का अभिन्न हिस्सा है. भारत समेत दक्षिण एशिया के अनेक देशों में उसकी हरकतों का संज्ञान वैश्विक स्तर पर भी लिया जाता रहा है. पर अफसोस की बात यह है कि प्रभावशाली देशों ने इस समस्या को अपने स्वार्थ के हिसाब से देखा है. जिसके कारण पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई नहीं हो सकी है. मसूद अजहर पर पाबंदी लगाने के सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर चीन का वीटो और पाकिस्तान में भारी निवेश, रूस द्वारा पाकिस्तान के साथ सामरिक समझौता करना, सामरिक आर्थिक सहयोग रोकने के बाद भी अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान मसले में पाकिस्तान को महत्व देना तथा ब्रिटेन द्वारा पाकिस्तान के भारत-विरोधी अभियान के लिए संसद परिसर के इस्तेमाल की अनुमति े देना इस रवैये के कुछ ठोस उदाहरण हैं. ऐसे में भारत को पाकिस्तान के बरक्स अपनी कुटनीति और रणनीति पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए.



# कैसा हो लक्ष्य

स जीवन को जीने के कई तरीके हैं. लक्ष्य तय करते हुए आप उसे हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं. सवाल है कि आप किस तरह के लक्ष्य तय करेंगे? दुनिया में कुछ ऐसा जिससे आप प्रभावित हैं या ुकुछ ऐसा जो आपने अभी तक नहीं किया है? आप जिन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप में आपकी जानकारी की सीमाओं के भीतर होते हैं. क्या यह दुखद नहीं है कि आप एक पूरा साल कुछ ऐसा हासिल करने की कोशिश में गंवा देते हैं, जिसके बारे में आप पहले से जानते हैं? मेरा इरादा यह है कि आप जो चीजें नहीं जानते, जिन चीजों की आपने पहले कभी कल्पना नहीं की है, उन्हें आपके जीवन में आना चाहिए. तभी आपका जीवन वास्तव में समृद्ध होगा. सिर्फ ऐसी चीजें करने का क्या फायदा, जो आप पहले से जानते हैं? मान लीजिए, आपके पास दस लाख डॉलर है और आपका लक्ष्य साल के अंत तक एक अरब डॉलर कमाना है. अगर ऐसा नहीं हो पाता, तो यह एक अच्छी चीज है, क्योंकि आपने उस उम्मीद में जीवन जिया. लेकिन अगर मान लीजिए जनवरी को ही ऐसा हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप उसे दस अरब डॉलर करना चाहेंगे. एक समय ऐसा था जब आप एक डॉलर से ही खुश हो जाते थे. अब उसी खुशी के लिए, आपको दस लाख डॉलर की जरूरत है. इसे इंफ्लेशन या मुद्रास्फीति कहते हैं. यह जीवन की बेहतरी नहीं है. यह जीवन जीने का कोई बुद्धिमानी भरा तरीका नहीं है. इसलिए पूरे साल का लक्ष्य तय करने की जगह, आप सिर्फ इतना ही तय कीजिए कि आज दिन के अंत तक, आपको थोड़ा और आनंदित, थोड़ा और बेहतर होना है. बीते हुए कल की शाम पर बस ध्यान दीजिए, 'क्या मैं कल के मुकाबले थोड़ा बेहतर हूं ?' बस इन चौबीस घंटों को ध्यान से देखिए, इससे आप अधिक चेतन हो पायेंगे. इसका मकसद आपको आनंदित या शांतिपूर्ण बनाना नहीं है. इसका मकसद है कि आप अपने जीवन के जितने संभव हो, उतने पहलुओं के प्रति चेतन हो जायें. सद्गुरु जग्गी वासुदेव

कुछ अलग

# अब बसंत आ गया है

वरिष्ठ व्यंग्यकार

puranika@gmail.com

बरांत पंचमी के पावन अवसर पर स्मार्ट विश्वविद्यालय द्वारा बसंत पंचमी विषय पर निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया. प्रथम पुरस्कार विजेता निबंध इस प्रकार है-

बसंत आ गया. क्यों आ गया यह सवाल निरर्थक है. बसंत चुनाव जैसा होता है या नेता जैसा, जो आ ही जाता है आप भले ही चाहें या न चाहें. बसंत आ गया पर कन्फ्यूजन है. कई जगह मौसम अब भी सर्दी वाला बना हुआ है. पर कई जगह गर्मी आ गयी है. बसंत का कोई नोटिस ही न ले रहा है कि भई ये भी आ गया है. बसंत कुछ-कुछ कर्नाटक के कांग्रेस विधायक जैसा फील कर सकता है, कोई नोटिस ही न ले रहा. कांग्रेस विधायक कर्नाटक में ऐसे नींव के पत्थर बने हुए हैं, जो परस्पर एक-दूसरे को कूट रहे हैं.

बसंत का प्राचीन साहित्य में बहुत महत्व बताया जाता था. बसंत के आसपास कुछ ऐसी हरकतों की शुरुआत होती थी, जिन्हें प्यार-मुहब्बत से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन तकनीक ने बारह महीने वसंत कर दिया है. अब तो फेसबुक पर कविगण इश्क वगैरह की कविताएं मचाये रहते हैं.

बसंत के आसपास वित्तीय वर्ष भी खत्म होता है 31 मार्च को. वेतनभोगी लोग इन दिनों जेब में भीषण लू भी फील कर सकते हैं. कर कटौती वेतन पर भारी पड़ जाती है. वेतन का हाल उस टीवी सीरियल से हो जाता है, जो बताया तो एक घंटे का जाता है, पर विज्ञापन वगैरह का टाइम काटने के बाद मुश्किल से 20 मिनट का बचता है. फरवरी के आसपास जो वेतन एक

आलोक पुराणिक

लाख का बताया जाता है, वह टैक्स कटौती के चलते 50 हजार का दिखता है. इस कटौती के मारे घनघोर वसंत में भी भयंकर लू फील होता है.

बसंत चेतना अब नयी पीढ़ी में गायब हो रही है. बसंत ज्ञान का पर्व

है- यह बात नयी पीढ़ी को बताओ, तो वह कहती है, व्हॉट्सएप पर तो ज्ञान पर्व रोज अहर्निश चौबीसो घंटे चलता है. वहां तो हर बंदा ज्ञान का थोक सप्लायर है. तो क्या हम मानें कि व्हॉट्सएप पर बसंत हमेशा ही रहता है? नयी पीढ़ी हर बात को अपने स्टाइल से समझती है. एक नौजवान ने बताया कि बसंत का महत्व इसलिए है कि ऐतिहासिक फिल्म शोले की एक नायिका का नाम बसंती था. बाकी ज्ञान-वान की नयी पीढ़ी को खास जरूरत नहीं है, वह तो व्हॉट्सएप पर लगातार बंट रहा है.

कुल मिला कर बसंत आम आदमी से हो लिया है, जिसे जो चाहे अपनी मर्जी से समझ ले. चुनावी दिनों में आम आदमी लोकतंत्र का राजा होता है. चुनाव बाद आम आदमी भीड़ का हिस्सा होता है. बसंत पर अतीत में कई काव्य रचे गये. बसंत आ गया है, जिसे जो रचना हो रचे. हालांकि, सोशल मीडिया के दौर में हर बंदा किव है. उसके लिए बसंत की प्रतीक्षा जरूरी नहीं. बसंत आ लिया है, फिर फागुन भी आयेगा. थैंक्स कि इन्हें लेकर कहीं दावे नहीं हैं कि हम ही बसंत फागुन लेकर आये. हमारे वक्त बसंत 10 फरवरी को आ गया, उनके वक्त में लेट आता था, आदि. तो मतलब बात ऐसी है कि जिसका जैसा चाहे, वह बसंत का वैसा इस्तेमाल कर सकता है.

# जलवायु परिवर्तन का कहर

न दिनों दुनियाभर में सर्दी ने कहर बरपा रखा है. अगर आपने पिछले कुछ दिनों की दिल्ली और उससे सटे इलाकों की तस्वीरें देखी हों. तो उनमें सड़कें और पार्क ओलों से पटे नजर आ रहे हैं. ऐसा दृश्य इससे पहले हाल-फिलहाल में देखने को नहीं मिला. जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में हर साल बर्फबारी होती है, लेकिन इस बार तो इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिये हैं. जम्मू कश्मीर में सर्दी का करीब तीन दशक पुराना रिकॉर्ड टूट गया है. इस बार उन पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी हुई है, जहां पिछले एक दशक में बर्फ नहीं गिरी थी. दक्षिण और पश्चिम भारत तक सर्दी नहीं पहुंचती थी, लेकिन इस बार सर्दी ने वहां तक मार की है. केवल भारत ही नहीं, आधी से ज्यादा दुनिया इन दिनों भीषण सर्दी की चपेट में है. अमेरिका, यूरोप सहित दुनिया के अनेक देश सर्दी का प्रकोप झेल रहे हैं. मौसम के कहर को देखते हुए अमेरिका के कई हिस्सों में आपातस्थित घोषित करनी पड़ी. अमेरिका के कई शहरों में तो तापमान शुन्य से 30 से 40 डिग्री तक नीचे चला गया था. शिकागो शहर में तापमान माइनस 23 डिग्री, उत्तरी डकोटा में शुन्य से 30 डिग्री नीचे और मिनेलोटा में सबसे कम शुन्य से 40 डिग्री नीचे तापमान दर्ज किया गया. यूरोप में भी हालात खराब हैं. चीन और कोरिया में भी सर्दी का कहर है. कुछ समय के लिए चीन की राजधानी पेइचिंग के सारे स्कूल बंद कर करने पड़े और लोगों से अनुरोध किया गया कि वे सड़कों पर बर्फ हटाने के काम में हाथ बंटाएं. वहां दशकों बाद सबसे अधिक हिमपात हुआ है. दक्षिण कोरिया भी सर्दी की चपेट में है. राजधानी सियोल को 70 वर्षों के बाद के सबसे अधिक हिमपात से जुझना पड़ रहा है. वहां भी कई हवाई अड्डों को बंद कर देना पड़ा. मौसम वैज्ञानिक इस असाधारण सर्दी के लिए ध्रुवीय तुफान को जिम्मेदार मान रहे हैं. आर्कटिक क्षेत्र में ध्रुवीय तूफान से हवाओं में उतार-चढाव के कारण ही दुनिया के उत्तरी हिस्से में भारी ठंड पड़ी है. वैज्ञानिक इस

वैश्विक शीतलहर को जलवायु परिवर्तन का नतीजा मान

रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियों का और

सामना करना पड़ सकता है. कुछ समय पहले जलवायु परिवर्तन को लेकर एक और चेतावनी सामने आयी है. नासा के अध्ययन में वर्ष 2018 को अब तक का चौथा सर्वाधिक गर्म साल बताया है. नासा के मृताबिक, 2018 में वैश्विक तापमान 1951 से 1980 के औसत तापमान से 0.83 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. 1880 के बाद से धरती की सतह का औसत तापमान तकरीबन एक डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है. नासा का कहना है कि यह गर्मी कॉर्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, ग्रीनहाउस गैसों और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ के कारण उत्पन्न हुई है. जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इस समस्या को गंभीर कर दिया है. जो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे सोख लेते थे, वह अब वातावरण में घुल रही है. दसरी ओर ब्रिटिश मौसम वैज्ञानियों ने चेताया है कि अगले पांच साल पिछले 150 वर्षों के मुकाबले सर्वाधिक गर्म रहेंगे. ब्रितानी वैज्ञानिकों के अनुसार, 2014 से 2023 के दशक में अगले पांच साल सर्वाधिक गर्म रहने के

आसार हैं. पूर्वानुमानों से जाहिर है कि दुनिया में तापमान में तेजी से वृद्धि होगी और औसत वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री तक की वृद्धि का अनुमान है. दरअसल, पिछली कुछ सदियों से हमारी जलवाय में लगातार बदलाव हो रहा है. इसका



आशुतोष चतुर्वेदी

ashutosh.chaturvedi

प्रधान संपादक, प्रभात खबर

@prabhatkhabar.in

वैज्ञानिक इस वैश्विक शीतलहर को जलवायु परिवर्तन का नतीजा मान रहे हैं . आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियों का और सामना करना पड़ सकता है . इसकी अनदेखी की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

> अच्छी बारिश होती है, बाढ आ जाती है. जलवाय परिवर्तन के दंश को परे देश को झेलना पड रहा है. ज्यादा बारिश होने के कारण कर्नाटक, उत्तराखंड, हिमाचल, असम और ओड़िशा के लोगों को भी भारी

अर्थ है कि सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ था, वह अब बदल रहा है.पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जलवायु में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण गर्मियां लंबी और सर्दियां छोटी होती जा रही हैं.

आपको याद होगा पिछले साल दक्षिणी राज्य केरल में पिछले 100 साल की सबसे विनाशकारी बाढ़ आयी थी. वैसे तो हर साल केरल में देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक बारिश होती है, लेकिन ऐसी तबाही की बारिश पहले कभी नहीं देखी गयी. पिछली बार केरल में लगभग 37 फीसदी अधिक बारिश हुई. पूरा राज्य भारी बारिश और बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ था. हर तरफ तबाही का मंजर था. राज्य में बिजली, पानी, रेल और सड़क व्यवस्था सब ठप हो गयी थी. अपने देश में पर्यावरण की अनदेखी आम बात है. अगर हम अपने आसपास देखें तो हम पायेंगे कि नदी के किनारों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और उसके आसपास इमारतें खडी होती जा रही हैं. इसके कारण नदी के प्रवाह में दिक्कतें आती हैं और जब भी

की समस्या नहीं होगी. बिहार की बात करें. तो दो दशक पहले तक बिहार में लगभग ढाई लाख तालाब हुआ करते थे. लेकिन आज इन तालाबों की संख्या घटकर लगभग 90 हजार रह गयी है. शहरों के तालाबों पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गयी और डेढ़ लाख के अधिक तालाब काल कलवित हो गये. उनके स्थान पर इमारतें खड़ी हो गयीं. नतीजा यह हुआ कि शहरों का जलस्तर तेजी से घटने लगा. हमने जल संरक्षण के उपाय करने जाने कब के छोड दिये हैं. बस्ती के आसपास जलाशय- तालाब, पोखर आदि बनाये जाते थे. जल को संरक्षित करने की व्यवस्था की जाती थी. लेकिन हमने अपने आसपास के तालाब मिटा दिये और जल संरक्षण का काम छोड़ दिया. चिंताजनक खबर यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण देश का औसत तापमान लगभग एक डिग्री सेल्सियस बढ़ जायेगा, जिसका सीधा असर खेती-किसानी पर पडेगा और पैदावार कम हो जायेगी. कृषि विशेषज्ञों का कहना है

# आपके पत्र

कि देश का एक डिग्री तापमान बढ़ने से पैदावार में 3 से 7

फीसदी की कमी आ जाती है. पर्यावरण का मसला सीधे

तौर से खाद्य सुरक्षा से जुड़ा है. इसलिए इसकी अनदेखी

की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है.

हाथी के मायने

# हाथी, सफेद हाथी और सियासी

किसी ने नहीं सोचा था कि हाथियों का भी राजनीतीकरण हो जायेगा. 'हाथी मेरे साथी' वाला भ्रम एक झटके में तोड़ दिया गया. निश्चित रूप से स्मारकों में लगे ये हाथी एक दिन विलुप्त जीव के रूप में दिखाने के काम आयेंगे. अनजाने ही वह भोला-भाला हाथी क्रमशः सफेद हाथी और सियासी हाथी में तब्दील होता चला गया. हाथियों के दुम पकड़े रहने वाली देश की मासूम जनता को क्या पता इस बड़े मुंह वाले जीव ने उनकी गाढ़ी कमाई का बड़ा हिस्सा ही खा लिया है. सुप्रीम कोर्ट पर चाहे जितनी उंगलियां उठें, इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए उसे बधाई तो मिलनी ही चाहिए, वरना पत्थर की मूरत चाहे जितनी ऊंची बना दें, कद तो बदहाल आम जनता का ही नापा जायेगा. मंदिर, मस्जिद के पत्थर हों या कश्मीर की गलियों के, लखनऊ के हाथी के हों या स्टेचु ऑफ यूनिटी के, सियासी पत्थरों ने हर बार जनता को ही चोट पहुंचायी है.

### अर्द्धसत्य ज्यादा खतरनाक

एमके मिश्रा, रातू, रांची

एक अंग्रेजी अखबार ने राफेल डील के बारे में एक खबर छापी, जिसने देश की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया. आरोप-प्रत्यारोप को नयी धार मिल गयी, परंतु अखबार ने जो रिपोर्ट छापी थी, उसमें पूरा सच नहीं था. उसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री की टिप्पणी बहुत ही चतुराई से छुपा दी गयी थी. अब अखबार ने ऐसा क्यों किया था, यह संपादक ही समझा सकते हैं, पर देश के रक्षा मामले से जुड़ा हुआ अर्द्धसत्य छापना एक बहुत बड़ी गलती है. इसको दलगत राजनीति से ऊपर रखना चाहिए. अखबार को अपना सामाजिक दायित्व समझना चाहिए. उसे समझना चाहिए कि सत्य जानने के लिए लोग अखबार पर निर्भर करते हैं. अखबार जिम्मेदार बने और जनता को गुमराह और दिग्भ्रमित होने से बचाना चाहिए.

सीमा साही, बोकारो

## शीर्ष कोर्ट की फटकार

शुक्रवार, सात फरवरी को सर्वोच्च अदालत ने बिहार और केंद्र सरकार को उनकी कार्यशैली पर जम कर लताड़ लगाया है. सबसे पहले तो सीबीआइ के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव पर कहा कि ईश्वर आपकी मदद करे. गौरतलब है कि राव ने ही सरकारी आश्रय घरों में बच्चियों के साथ की गयी ज्यादती की निगरानी करने वाले अधिकारी एके शर्मा का अदालत की इजाजत के बगैर स्थानांतरण कर दिया था. अब इन्हें जो जवाब देना है, वह दें, मगर बिहार की नीतीश सरकार पर भी शीर्ष अदालत ने कड़ा प्रहार किया है. आश्रय घर की जांच को बिहार से स्थानांतरित करके दिल्ली के साकेत कोर्ट में भेजने का आदेश देना बिहार सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब है. पहले दिन से ही स्थानीय सरकारी महकमा इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था, अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया जा रहा था. शीर्ष कोर्ट के दबाव के बाद ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

# संसद में बसवन्ना, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर सद में समय-समय पर नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, कवियों की 'लहर' पत्रिका में 'चौराहे' शीर्षक से प्रकाशित हुई थी.



रविभूषण वरिष्ठ साहित्यकार

ravibhushan1408@gmail.com

नेताओं के मुख से जब काव्य-पंक्तियां निकलती हैं, तो नेताओं की मंशा कुछ और ही होती है . कविता का मर्म और अर्थ उनकी समझ से परे होता है.

काव्य-पंक्तियां पढ़ कर तालियां बटोरते रहे हैं. कविता और कवियों से उनका लगाव नहीं होता, पर यह सिलसिला लंबे समय से चल रहा है. वित्त मंत्री अपने बजट-भाषण में कवियों को याद करते रहे हैं. क्या हम इसे राजनीतिक दलों का कवि-प्रेम या काव्य प्रेम मान लें या यह केवल हल्के-फुल्के अंदाज में उनके द्वारा उद्धृत काव्य-पंक्तियां हैं? अंतरिम वित्त मंत्री पीयुष गोयल ने अपने बजट-भाषण में मुक्तिबोध का नाम लिये बगैर उनकी एक कविता 'मुझे कदम-कदम पर' की दो पंक्तियां पढ़ी, वह भी गलत. कविता की आरंभिक पंक्तियां हैं, 'एक पैर रखता हूं/ कि सौ राहें फूटतीं/ व मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूं.' वित्त मंत्री ने 'पैर' को 'पांव' बना दिया और 'सौ राहें' 'हजार राहें' बन गयीं. भाषण का समापन 'एक पांव रखता हूं, हजार राहें फूट पड़ती हैं' से किया. यह भी कहा, 'हिंदी के बहुत विख्यात कवि थे, बहुत प्रगतिशील माने जाते थे. हिंदी में कविता करते थे, पर मूलतः महाराष्ट्र से आते थे, जहां से मैं भी आता हूं.' इसके बाद उन्होंने नये भारत के निर्माण के लिए नये सशक्त प्रभावी कदम उठाने की बात कही, जिससे 'आज भारत हर क्षेत्र में दुनिया के स्तर पर अनेक संभावनाओं से भरा देश माना जाता है.' कवि का नामोल्लेख उन्हें आवश्यक नहीं लगा.

मुक्तिबोध की पुस्तक 'भारत : इतिहास और संस्कृति' पर कानूनी प्रतिबंध लगाने और जलाने की मांग जबलपुर में 1962 में उठी थी. रायपुर में जनसंघ ने मुक्तिबोध के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था और कई आरोप लगाये थे. अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र 'ऑर्गनाइजर' ने उनके खिलाफ लेख लिखा था और दीनदयाल उपाध्याय ने मुक्तिबोध को 'विकृत मस्तिष्क' का लेखक कहा था. मुक्तिबोध ने उसी समय यह लिखा था, 'दक्षिणपंथी उग्र सांप्रदायिकता या धर्मवाद इतिहास के शास्त्रीय क्षेत्र में जोर आजमाना चाहता है.' आज के खतरों को उसी समय मुक्तिबोध ने पहचान लिया था. उन्होंने 'तीन बड़े खतरों' की बात कही थी- लेखक की निजी लेखकीय स्वतंत्रता, विचार स्वतंत्रता को खतरा, इतिहास शास्त्र को अशास्त्रीय रचना से खतरा और शास्त्रीय क्षेत्र में, शास्त्रीय क्षेत्र के प्रकाशनों में शासन के हस्तक्षेप से खतरा. उस समय 1962 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी. आज केंद्र में भाजपा की सरकार है. उस समय मुक्तिबोध ने सांप्रदायिक दल और उग्र दक्षिणपंथियों की पहचान कर ली थी. एक पैर रखने पर मुक्तिबोध के यहां जो सौ राहें फूटती हैं, वे सामान्य नहीं हैं. इसी कविता में वे 'प्रत्येक वाणी में महाकाव्य-पीड़ा' देखते हैं. इस कविता का संभावित रचना-काल नेमिचंद्र जैन ने 1959-60 माना है और यह कविता दिसंबर 1961 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक कई बार 12वीं सदी के लिंगायत

दार्शनिक, महान कन्नड़ कवि, समाज सुधारक और क्रांतिकारी बसवन्ना को अपने भाषणों में याद किया है. इस बार उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने धन्यवाद भाषण में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा पढ़े गये बसवन्ना के कुछ वचनों पर यह कहा- 'मैं चाहूंगा कि हर कांग्रेसी घर में बसवन्ना का वचन संजो कर रखें और अभी-अभी जहां सरकार बनाने का आपको मौका मिला है, वहां तो बड़े अक्षरों में लगाकर रखें.' दक्षिण राज्यों में कर्नाटक में ही भाजपा की सरकार रही है. क्या सचमुच भाजपा बसवन्ना से कुछ सीख पायी? बसवन्ना ब्राह्मण थे, पर वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध थे. उन्होंने सामाजिक भेद-भाव को अस्वीकृत किया अंधविश्वास और धार्मिक कृत्य, अनुष्ठान की आलोचना की, नयी लोक लोकसंस्थाएं बनायीं. बसवन्ना के नामोल्लेख भर से कोई उनके आदर्शों पर नहीं चल सकता. हम जिसे आचरण की पवित्रता-शुचिता कहते हैं,

उससे भारतीय राजनीति का कोई रिश्ता नहीं है. प्रधानमंत्री ने बसवन्ना का नाम तो लिया, पर सर्वेश्वरदयाल सक्सेना का नहीं, जिनकी काव्य-पंक्तियां उन्होंने उद्धत कीं. बारहवीं सदी के

बसवन्ना ही नहीं, बीसवीं सदी के मुक्तिबोध और सर्वेश्वर भी आज 'अर्बन नक्सल' बता दिये जाते. खड़गे ने अपने भाषण में सर्वेश्वर की काव्य-पंक्तियां पढ़ी थीं- 'ये हुस्न-ओ-आब तो ठीक है/ लेकिन गुरूर क्यों तुमको इस पर है/ मैंने सूरज को हर शाम इसी/ आसमां में ढलते देखा है.' एक शब्द 'हुस्न' को उनके सामान्य अर्थ में रखकर नरेंद्र मोदी ने सवाल किया, 'मुझे समझ नहीं आया कि उनको हुस्नवाली पंक्ति क्यों पसंद आयी?' न उन्हें 'गुरूर' शब्द याद रहा और न 'सूरज का ढलना'. कविता का अगला अंश उन्होंने पढ़कर सुनाया, जिसमें झूठ की बस्ती में सच को तड़पते देखने, अपने भीतर बच्चे के सिसकने आदि की बात थी. कविता की पंक्तियां एक-दूसरे से अविच्छिन्न हैं, पर मोदी ने उन्हें एक-दूसरे के विपरीत ला खड़ा किया. अपने मनोनुकूल पंक्तियां दोहरा दीं और उनका आरंभिक पंक्तियों से संबंध नहीं माना. अपने भाषण के अंत में पुनः उन्होंने सर्वेश्वर की कविता, 'मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा' की पंक्तियां पढ़ीं, जो कविता की अंतिम पंक्तियां हैं. कवि ने किसी भी सूरज को 'न डुबने देने' की बात कही थी. प्रधानमंत्री ने 'सुरज' का अर्थ और संदर्भ बदल दिया, अपने पक्ष और हित में उसे रख दिया. यह कविता का अर्थ है या अनर्थ, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता. नेताओं के मुख से जब काव्य-पंक्तियां निकलती हैं, तो उनकी मंशा कुछ और ही होती है. कविता का मर्म और अर्थ उनकी समझ से परे होता है.

## देश दुनिया से कार्ट्रन कोना

# चीन की परियोजना से ग्वादर की जनता नाराज

**चीन** की ग्वादर परियोजना से स्थानीय पाकिस्तानी जनता नाराज है. यह परियोजना चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे या सीपीइसी के अंतर्गत चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर व ऊर्जा परियोजनाओं का हिस्सा है. विशेषज्ञ इसको पाकिस्तान के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं. लेकिन, ग्वादर का स्थानीय मछुआरा समुदाय इससे खुश नहीं है. चीन ने ग्वादर बंदरगाह के पास ही व्यापारिक केंद्र स्थापित किया है. स्थानीय मछुआरों के अनुसार, अगर कोई

मछुआरा प्रतिबंधित क्षेत्र के

पास पकड़ा गया, तो गार्ड उनकी पिटाई तक करते हैं. भारत भी इस परियोजना से खुश नहीं है. भारत के अनुसार, यह परियोजना क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन करती है. दरअसल, यह इलाका विवादित क्षेत्र पाकिस्तान प्रशासित जम्मू-कश्मीर क्षेत्र का हिस्सा है. हालांकि, चीन और पाकिस्तान, दोनों भारत की आपत्ति को खारिज करते हैं. मछुआरा समुदाय इससे परेशान है. उनके अनुसार, वे इलाके में न अपनी नाव लगा सकते हैं, न सफाई कर सकते हैं और परियोजना के तहत जहां सड़क बन रही है, वहां के समुद्र तट के पास जाने पर भी रोक है. अधिकारियों ने मछुआरों के सागर में जाने के लिए सड़क के नीचे से होकर 12 फीट चौड़ी तीन सुरंगें बनाने का प्रस्ताव रखा है.

# ⊕\$060 Q€Q#1

साभार : कार्टूनमूवमेंटडॉटकॉम

**पोस्ट करें** : प्रभात खबर, १५ पी, इंडस्ट्रियल एरिया, कोकर, रांची ८३४००१, **फैक्स करें** : **०६५१–२५४४००**६, मेल करें: eletter@prabhatkhabar.in पर ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है